ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-8* October- 2020
Innovation The Research Concept

भारत में दलीय व्यवस्था : एक अध्ययन

Party System In India: A Study

Paper Submission: 10/10/2020, Date of Acceptance: 25/10/2020, Date of Publication: 26/10/2020

राजेश कुमार
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
रा.च.उ.राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड़, भारत

सारांश

दलीय व्यवस्था राजनीतिक दलों के महत्ता को सूचित करती है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में एक दल दूसरे से सम्बन्धित होते हैं चाहे वह प्रारम्भिक स्तर का दल हो या प्रतिस्पर्द्वात्मक स्तर का, दोनों ही स्तर पर दल एक–दूसरे के विरोधी होते हैं। सभी राजनीतिक दल देश की राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था से सम्बन्धित होते हैं दलीय व्यवस्था के अंग भी होते हैं। आजादी के बाद अब तक सम्पन्न हुए 17 वीं लोकसभा चुनाव तथा समय–समय पर सम्पन्न हुए विधान सभाओं के चुनाव में वर्तमान दलीय व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए खासकर (1989) गठबन्धन के युग का प्रारम्भ, इसने देश की चुनावी राजनीति में एकदलीय प्रधानता की जगह गठबन्धन की प्रधानता को स्थापित किया है।

Party system informs the importance of political parties. In a democratic system, one party is related to the other, whether it is the initial level party or the competitive level, both parties are opposed to each other at the same level. All political parties are related to the politics and constitutional system of the country are also part of the party system. In view of the situation of the present party system in the 17th Lok Sabha Elections held after Independence and the elections to the Legislative Assemblies held from time to time, especially (1989) the era of coalition started, it replaced the one-party dominance in the electoral politics of the country. Has established the primacy of coalition.

मुख्य शब्द : दलीय व्यवस्था, राजनीति, समुदाय, लोकतान्त्रिक व्यवस्था ।
Party system, politics, community, democratic system.

प्रस्तावना

व्यक्यिों के किसी ऐसे समूह को जो एक सामान्य उद्देश्य कि प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, उसे समुदाय या संगठन कहते हैं। समाज में इस प्रकार के संगठन आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। जब राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा संगठन बनता है या कार्य करता है तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल उन सभी व्यक्तियों के समूह को कहते है जिनका राजनीतिक उद्देश्य एक समान होता है। वे अपने विचारों का जनता में प्रचार करके अपने पक्ष में जनमत जगाना चाहते हैं और अपने विचारानुसार सरकार बनाकर उसे चलाना चाहते हैं। इस प्रकार राजनीति दल एक राजनीतिक संगठन है, जिसका उद्देश्य सरकार बनाकर शासन करना होता है।

भारत मे राजनीतिक दलों का विकास भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व गिने–चुने ही राजनीतिक दल थें और उनका सरकार में कोई विशेष प्रभाव नहीं था ये दल दबाव समूह या गूट–समूह से अधिक कुछ नहीं था इनका प्रयोग सामाजिक,आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए आंदोलन के रूप में ही होता था। भारत में राजनीतिक दलों का विधिवत् स्वरूप कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। आरम्भ में कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं था। 1885 मे इसका निर्माण एक दबाव गुट के रूप में किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारतवासियों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएँ प्राप्त करना था। गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक राष्ट्रव्यापी जन–आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न जाति, धर्म और आदर्शों को मानने वाले लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कांग्रेस में शामिल हो गये। 1947 तक यह संघर्ष एक विदेशी राजनीतिक सत्ता और भारतवासियों के बीच रहा, इसलिए भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों ने इस आंदोलन में संगठित होकर भाग लिया, 1947 के बाद भारतीय कांग्रेस ने वास्तविक अर्थों मे एक राजनीतिक दल का

रूप धारण किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में राष्ट्रीय स्तर के दो ही दल थें–भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका संगठन व्यापक और विशाल था। दूसरा साम्यवादी दल था जो एक सीमित स्तर पर कार्य कर रहा था बाद मे धीरे–धीरे अन्य दलों का विकास हुआ। कांग्रेस के निर्माण के कुछ ही वर्षों बाद मुस्लिम लीग जो एक सांप्रदायिक संगठन कि स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना की प्रतिक्रिया के रूप मे एक अन्य सांप्रदायिक संस्था हिन्दू महासभा का गठन 1916 मे हुआ था इस दल का उद्देश्य पूर्ण स्वराज प्राप्त करना तथा हिन्दू राष्ट्र की स्थापना करना था। 1962 से 1967 के बीच बहुत से दलों का एक दूसरे में विलय हुआ, कुछ का विघटन हुआ। परिणाम स्वरूप नये–नये दलों का भी उदय हुआ। इन दलों के अतिरिक्त विभिन्न प्रदेशों मे प्रादेशिक राजनीतिक दलों की भी स्थापना हुई जैसे उत्तर प्रदेश कृषक पार्टी, पंजाब मे युनियानिस्ट पार्टी, चेन्नई मे जस्टिस पार्टी आदि।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 1924 मे ही साम्यवादी दल की स्थापना हुई। स्वतंत्र भारत कि राष्ट्रीय स्तर की पहली राजनीतिक पार्टी जनसंघ कही जाती है जिसकी स्थापना 1951 मे हुई थी। इसी प्रकार 1949 मे ही डीएम के,1950 मे भारतीय समाजवादी दल, किसान मजदूर प्रजापार्टी कि स्थापना हुई इस प्रकार 1952 के आम चुनावों मे 14 दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर एंव 51 दलों ने प्रादेशिक स्तर पर चुनाव में हिस्सा लिया। स्वतंत्र भारत मे 1959 मे कांग्रेस दो भागों मे विभाजित हो गयी। इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई काग्रेस, जो इन्दिरा कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। 1971 के मध्यावधि लोक सभा की 518 सीटों में से 350 सीटें जीती जबकि पुरानी कांग्रेस को 16 स्थानीय सीटें मिल सकी। 1972 मे सोशलिस्ट पार्टी व प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पुनः एक हो गयी। और उसका नाम सोशलिस्ट पार्टी आफ इण्डिया हुआ।

1977 में देश की राजनीति परिदृश्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन उस समय हुआ जब देश की बागडोर संभालने वाली कांग्रेस दल का विरोधी दल जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी ने श्री मोरारजी देसाई को अध्यक्ष बनाया आपातकाल कि विभीषिका को भुगतने के पश्चात् 1977 के आम चुनाव मे जनता को जनता पार्टी की सरकार का गठन कराने के लिए बाध्य होना पडा। चुनाव आयोग ने भी जनता पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे दी। जनता पार्टी में विभाजन के फलस्वरूप 15 जुलाई 1979 को जनता पार्टी की सरकार का भी पतन हो गया। 1980 मे इन्दिरा गाँधी पुनः देश की प्रधानमंत्री बनी, उनके दल को आशातीत बहुमत प्राप्त हुआ। 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में हुए निर्वाचनों में कांग्रेस पार्टी को पुनः सफलता मिली।

1989 और 1991 में कांग्रेस लोक सभा चुनावों में सर्वाधिक स्थान प्राप्त की परन्तु बहुमत नहीं पा सकी। 1989 में एक बार फिर सत्ता गैर–कांग्रेसी अल्पमत साझा सरकार के हाथों में चली गयी। केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वी.पी. सिंह की सरकार का गठन हुआ। 1991 में पी.वी नरसिम्हा राव के नेतृत्व पूरे 5 वर्ष (1991–1996) एक अल्पमत सरकार का गठन किया जिसने अपना कार्यकाल छोटे दलों के सहयोग से पूरा किया। 1996 मे हुये ग्यारहवीं लोकसभा के चुनावों के नतीजों से केन्द्र मे अस्थायी गठबंधन वाली सरकारों की स्थापना हुई और इस लोक सभा कि अवधि में देश को तीन प्रधानमंत्री मिले, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, तथा इन्द्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा, इन्द्र कुमार गुजराल कि सरकारें भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी, क्योंकि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया।

फरवरी 1998 में बारहवीं लोकसभा चुनाव में वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकारें बनी लेकिन गठबंधन के आपसी कलह के कारण यह एक साल तक ही चल सकी। अक्टूबर 1999 में सम्पन्न तेरहवीं लोकसभा के चुनावी नतीजों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के मुख्य घटक होने कि वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व मे केंद्र मे एक बार फिर पुनः सरकार का गठन हुआ। नम्बर– दिसम्बर 2003 में देश की पांच विधान सभाओं के चुनाव परिणामों से उत्साहित होकर केन्द्र कि राजग सरकार ने भारत की 14 वीं लोकसभा के चुनाव समय से पूर्व ही कराने का इरादा किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनावों में भाजपा के पक्ष मे आये मतदाताओं के रूझान को आम चुनाव के लिए अच्छा संकेत मानते हुये भाजपा और उसके सहयोगी दल आम चुनाव के लिए सितम्बर 2004 तक कि प्रतीक्षा करने के मूड मे नहीं थे। इसी परिपेक्ष्य में तेरहवीं लोकसभा को 6 फरवरी 2004 से ही भंग करने कि संस्तुति करने का निर्णय केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के बैठक में लिया गया। 2004 में सम्पन्न 14 वीं लोकसभा के .चुनाव में दलीय व्यवस्था मौटे–तौर पर दो नेता अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गॉधी, दो दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तथा दो गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के बीच आमने–सामने की राजनीति प्रतियोगिता और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच बंटी देखी गई, 2004 में (UPA) की सरकार बनी और डॉ0 मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने (2004–2009) 15वीं लोकसभा के चुनाव के लिए अप्रैल–मई 2009 में पांच चरणों में सम्पन्न चुनावों मे सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) ने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की, जिसके चलते पहले से भी अधिक शक्ति के साथ (UPA) ने सत्ता में वापसी की तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बार पुनः प्रधानमंत्री के रूप में सरकार की कमान संभाली। (इसमें कांग्रेस 206 तथा सहयोगी दल को लेकर 322 सांसदों का समर्थन शपथ ग्रहण से पूर्व ही प्राप्त हो गया था)

16 वीं लोकसभा का चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त की अकेले भाजपा को 282 सीटें मिली, उनकी सहयोगी दलों (एनडीए) को 327 सीटें इस चुनाव में प्राप्त हुई, जबकि कॉग्रेस पार्टी को 44 सीटें मिली लोकसभा के 10% से कम सीटें होने के कारण कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद भी प्राप्त नहीं हो सका। इस चुनाव में (यूपीए) की संख्या 58 थी।

17 वीं लोकसभा का चुनाव भाजपा ने एक बार पुनः नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और सफलता प्राप्त की। 17 वीं लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच सात चरणों में आयोजित कराये गये चुनाव परिणाम 23 मई को घोषित किये, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की और अपना पूर्ण बहुमत बनाये रखा और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबन्धन ने 553 सीटें जीतीं। भाजपा ने 37-36 प्रतिशत वोट हासिल किए, जबकि एनडीए का संयुक्त वोट शेयर 60.37 करोड़ वोटों का 45 प्रतिशत था। इस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबन्धन ने 92 सीटें जीती। अन्य दलों और उसके गठबन्धन ने भारतीय संसद में 97 सीटें जीती।

शोध का उददेश्य

1. भारतीय दलीय व्यवस्था का इतिहास।
2. लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका का अध्ययन।
3. लोकतान्त्रिक व्यवस्था में विरोधी दलों की भूमिका क्या होती है?
4. सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में दबाव समूहों की भूमिका का पता लगाना
5. भारतीय दलीय व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों की भूमिका
6. जनता की राजनीति सहभागिता का पता लगाना।
7. मतदाताओं के मतदान व्यवहार का अध्ययन करना
8. गठबन्धन की समस्या किस प्रकार राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुँचाती है?
9. भारतीय दलीय व्यवस्था की वर्तमान प्रवृतियाँ।

निष्कर्ष

दलीय व्यवस्था, राजनीतिक दलों के आकर्षण और उसकी महत्ता को सूचित करती है लोकतान्त्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वे महत्वपूर्ण सामाजिक मांगों को पूरा करने का एक माध्यम हैं। ये सरकारी जिम्मेदारियों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि संसदीय व्यवस्था और नीतियों की स्थितियों और चुनौतियों को संगठित किया जा सके।

सन्दर्भ सूची

1. *सिंहल, एस. सी. (2016–17) भारतीय शासन एवं राजनीति, नवरंग ऑफसेट प्रिन्टर्स आगरा पृष्ठ संख्या 250 से 255*
2. *बिस्वाल, तपनः गिरि, मधुस्मिता, तुलनात्मक राजनीति संस्थाएं और प्रकियाएं, ओरियन्ट ब्लैक स्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली पृष्ठ संख्या 359 से 361*
3. *त्रिवेदी, आर.एन., राय.एम.पी भारतीय सरकार और राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1998 पृष्ठ संख्या 256 से 257*
4. *एस.एस. सदाशिवम पार्टी एण्ड डेमोक्रेसी इन इंडिया, मेक्सग्राहिल पब्लिशिंग नई दिल्ली 1977 पृष्ठ संख्या 5*
5. *रजनी कोठारी पोलिटिक्स इन इंडिया, पृष्ठ संख्या 200*
6. *सुशीला कौशिक, भारतीय शासन व राजनीति हिन्दी क्रियान्वयन माध्यम दिल्ली वि. वि. 1990 पृष्ठ संख्या 329*
7. *पाठक, नरेन्द्र (सम्पादित) विकसित बिहार की खोज, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 2010*